दोनों बन्द पड़े हुए हैं । उनकी वजह से आज इतनी बड़ी बिजली की कठिनाई और संकट राजस्थान को झेलना पड़ रहा है । उसके बारे में सदन में हर साल यही मसला उठता है और सरकार आश्वासन देती है पर हर साल कुछ नहीं हो पाता है ।

माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसके बारे में कुछ किया जाए ताकि उद्योग को कुछ तो बिजली मिले । शत-प्रतिशत पावर-कट में उद्योग कैसे चल सकेगा, यह भी आप ख्याल कर लें ।

REFERENCE TO THE ACUTE POWER SHORTAGE IN THE COUNTRY CAUSING GREAT HARDSHIP TO ENTREPRENEURS

SHRI HUSEN DALWAI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to mention the following matter of urgent public importance.

Sir, in the entire country there is an acute shortage of power. The policy of the Government to encourage the industry has come to such a stage that the new entrepreneurs who have started their new undertakings are not getting power. They have been financed by the financial institutions. They are unable to pay the instalments and they want that they should be assured of this power. As a matter of fact, the Planning Commission and the Government of India have not visualised what would be the requirement of power when the policy of industrialisation was enunciated. In every State there are three districts which have been declared as backward districts. And there, an encouragement has been given by all financial institutions and new people have come to start industries, and they are progressing. The new proposals which have been taken in hand by the Government and by various Electricity Boards are lagging behind and their planning is still at a backward stage. And I don't think that they will be able to meet the requirements in a short time. As a matter of fact, there was a policy in between that the Government of India has taken a decision not to encourage hydro-electric projects because of investment. They were costly. But as a matter of fact the thermal projects which have been taken in hand, because of the short supply of coal, because of the non-availability of the wagons, these things have come in the way and there is acute shortage in every State. I would like to request the Government of India and especially the Ministry of Energy to take a note of this thing and see that these things which are taken in hand are expedited.

REFERENCE TO THE ALLEGED THREAT OF THE US GOVERNMENT TO WITHDRAW ITS MEMBERSHIP FROM UNESCO

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सी यूनेस्को से यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ने अपनी सदस्यता छोड़ देने की जो धमकी दी है उस ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी इस उद्देश्य से कि दुनिया के देशों के अन्दर भाईचारा बढ़े और साथ ही साथ दुनिया के लोगों का जो जीवन स्तर है उस को किस तरह बढ़ाया जाय, जहां शिक्षा नहीं है वहां शिक्षा दी जाय । मान्यवर, आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या के लोगों के बच्चे आज स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं। यूनेस्को ने इस बात का फैसला किया कि 1980 तक 200 मिलियन बच्चों को स्कूलों में भेजने की व्यवस्था करेंगी और उस के लिए सुविधाएं देंगी । बहुत काफी काम हुआ है पिछले चन्द सालों के अन्दर चाहे वह संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च का क्षेत्र हो । ऐसी स्थिति में जो दुनिया में जनकल्याण के कार्यों में संस्था लगी हो उस का राजनैतिक दृष्टि से प्रयोग किया जाए और जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ने निकल जाने की धमकी दी है उस से इस बात का पता